भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2744
दिनांक 02.08.2022/ 11 श्रावण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

एमओएस के अंतर्गत विकास परियोजनाएं

†2744. श्री होरेन सिंह बे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2011 में यूपीडीएस, असम राज्य सरकार और केन्द्र सरकार और वर्ष 2021 में कार्बी सशस्त्र समूह, असम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ हस्ताक्षरित एमओएस (मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट) के अनुसार सभी विकास परियोजनाओं (खंड-वार) को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं में विलंब के कारणों की जांच की है;
(ग) यदि हां, तो क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने एमओएस, 2011 एमओएस, 2021 की इन स्वीकृत परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोई त्वरित योजना विकसित की है या कोई समर्पित निधि बनाई है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ड.): सरकार ने भारत सरकार और असम सरकार के साथ "यूनाइडेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी (यूपीडीएस)" के प्रतिनिधियों द्वारा 25 नवम्बर, 2011 को हस्ताक्षरित और "कार्बी समूहों" के प्रतिनिधियों द्वारा 04 सितंबर, 2021 को हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओएस) के कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर), असम सरकार की सिफारिशों के आधार पर इन समझौता ज्ञापनों के तहत विकास परियोजनाओं को मंजूरी देता है। भारत सरकार, इन समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन की असम सरकार और अन्य हितधारकों के साथ नियमित रूप से समीक्षा करती है।

*****